आतंकवाद के सवाल पर नाकाम हुकूमत

परत-दर-परत

प्रभात कुमार रॉय

खूनी काले बुधवार के दिन बर्बर आतंकवादी मुंबई महानगर पर बर्बर खूनी निशाना लगाने में एक बार फिर से कामयाब हो गए। सन 1993 में प्रथम बार मुंबई महानगर पर ब्लैक ब्लडी वेडनसडे को ही जेहादी आतंकवादियों ने बर्बर आक्रमण अंजाम दिया था। तब से तकरीबन 14 बार मुंबई महानगर पर आतंकवादी आक्रमण अंजाम दिए गए। आतंकवाद के गहन प्रश्न पर हुकूमत ए हिंदुस्तान को नाकाम करार दिया जा सकता है। जेहादी आतंकवाद यकीनन सदैव एक अंतरराष्ट्रीय मसला रहा, किंतु अमेरिका को जेहादी आतंकवादी महज एक मर्तबा ही अपना बर्बर निशाना बना सके। 9-11 के आतंकवादी आक्रमण के पश्चात अमेरिका को जेहादियों द्वारा पुनः कदाचित निशाना नहीं बनाया जा सका। अमेरिका ने अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति को जेहादी आतंकवाद के तमाम गढ़ों को तहस-नहस करने में झोंक दिया। किंतु इसके विपरीत भारत जिसने अपने सीने पर विगत 23 वर्षों से जेहादी आतंकवाद के वहशियाना हाथों से सबसे अधिक जख्म झेले, आतंकवाद से आर-पार की जंग करने की राजनीतिक इच्छा कदापि नहीं प्रदर्शित किया। जब कभी और कहीं आतंकवादी आक्रमण हो जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के साथ समूचा राष्ट्र कुछ दिनों के लिए जाग गया। कुछ वक्त व्यतीत हो जाने के पश्चात और अगला आक्रमण होने तक अजगरी निद्रा में सभी सो जाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के बरखिलाफ मुसलसल तौर से जिस तरह की राष्ट्रीय चेतना और सजगता की सदैव दरकार रही, ऐतिहासिक रुप से इसका मुकम्मल अभाव रहा। केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम ने दो साल पूर्व एंटी टैररिस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव किया, किंतु प्रस्ताव सरकारी फाइलों से आगे नहीं बढ़ सका। आतंकवाद पर नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) के गठन के बावजूद केंद्र और प्रांतीय सरकारों की खुफिया ऐजेंसियों के मध्य बेहद जरूरी तालमेल का गहन अभाव कायम रहा। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मसला कदाचित कानून-व्यवस्था का मामूली सवाल नहीं, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र हुकूमत राष्ट्र को प्रांतीय सरकारों को सौंपकर निश्चिंत हो जाए। राष्ट्र के संपूर्ण खुफिया नेटवर्क को सुनिश्चित तालमेल के साथ कारगर तौर से इस्तेमाल करने का दायित्व केंद्रीय हुकूमत का है। भारतीय राजसत्ता ने राष्ट्र की खुफिया एजेंसियों को भौतिक और नैतिक रुप से सदैव ही बेहद कमजोर बनाए रखा गया। जहां अमेरिका में एक लाख की आबादी पर औसतन 100 खुफिया एजेंट्स तैनात रहे, वहीं रशिया एवं चाइना में एक लाख की आबादी पर औसतन 150 खुफिया एजेंट्स की तैनाती बनी रही। इसके विपरीत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के सर्वोच्च निशाने पर कायम रहे भारत में एक लाख की आबादी पर औसतन मात्र 10 खुफिया एजेंट्स ही तैनात रहे। प्रत्येक आतंकवादी आक्रमण के पश्चात प्रायः इसे खुफिया तंत्र की नाकामी करार दिया जाता रहा। भारतवर्ष पर निरंतर जारी रहे आतंकवादी आक्रमण का कारण दरअसल संपूर्ण राष्ट्र की गंभीर अक्षम्य राजनीतिक-सामाजिक विफलता रही। भारतीय राजसत्ता के शिखर पर विराजमान राजनेताओं को अमेरिका और चाइना की तरह ही, विश्वस्तर के बेहद ताकतवर खुफिया नेटवर्क का सृजन करने से आखिर रोक कौन रहा है? अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से मुकाबला करने वाली भारत की इंटरनेशनल खुफिया ऐजेन्सी रॉ की कतारों में केवल कुछ हजार ऐजेंट्स ही विद्यमान रहे, जबकि पाकिस्तान की आइएसआइ की कतारों में एक लाख से अधिक ऐजेंट्स सदैव मौजूद रहे।

आज देश की संसद में विपक्ष में विराजमान राजनेता पूरे छः वर्षों तक, 1998 से 2004 तक बाकायदा केंद्रीय राजसत्ता पर काबिज बने रहे। अंतरराष्ट्रीय जेहादी आतंकवाद के जटिल प्रश्न पर लचर-मचर शासकीय नीति पर मनमोहनी यूपीए हुकूमत कायम रही, तकरीबन ऐसी शासकीय नीति अटल जी की एनडीए सरकार की भी रही। अमेरिका के कूटनीतिक दबाव में पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ उन्होंने बेहद नरम रवैया अख्तियार किया और उनके मूल चरित्र को कदाचित संज्ञान में न रखते हुए, उन पर गैर जरूरी भरोसा किया गया। परिणामस्वरुप कूटनीतिक बातचीत के आगोश में पाक सेना ने जेहादियों को आगे कर कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा किया। ऐतिहासिक गलतियों से कदाचित कोई सबक न सिखकर मनमोहनी यूपीए हुकूमत पुनः वही भूल दोहराने पर आमादा है। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के कूटनीतिक दबाव के तहत कभी कश्मीर को बलपूर्वक हड़पने की शासकीय नीति का परित्याग कर दिया? क्या पाकिस्तान ने कश्मीर जेहाद का संचालन करने आतंकवादी जेहादी गुटों को प्रश्रय प्रदान करना बंद कर दिया? क्या पाक-अधिकृत कश्मीर में आइएसआइ ने बाकायदा शासकीय नीति के तहत आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को बंद कर दिया? यदि नहीं तो फिर आखिर किस ठोस धरातल पर वार्ता का कूटनीतिक आयोजन जारी है। भारत को संजीदगी के साथ यदि आतंकवाद से निपटना है तो कूटनीतिक दबावों को दरकिनार करते हुए अपने गहन राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अपनी शासकीय नीति का फिर से निर्माण करना होगा। दलगत पूर्वाग्रहों और राजनीतिक मौकापरस्ती का परित्याग करके आतंकवाद के प्रश्न पर राष्ट्रीय सहमति का तत्काल सृजन होना चाहिए। भारतीय खुफिया नेटवर्क को विश्व स्तर का बनाने के लिए बेहद कड़े प्रयास किए जाने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को किसी खास मजहब से संबद्ध करके देखने की प्रवृति का खात्मा होना चाहिए। इसके लिए साहिर लुधियानवी की पंक्तियों का स्मरण करें

किसी बर्बर की कोई कौम न,
कोई मजहब न, कोई जात
उसके लिए इन अल्फाज का
जबान पर लाना हराम है।

मोबाइल:09319310533

दलगत पूर्वाग्रहों और राजनीतिक मौकापरस्ती का परित्याग करके आतंकवाद के प्रश्न पर राष्ट्रीय सहमति का तत्काल सृजन होना चाहिए

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission